3. स्फीति अन्तराल (THE INFLATIONARY GAP)

1940 में प्रकाशित अपने How to Pay for the War पैम्फ्लेट में केन्ज ने स्फीति अन्तराल की धारणा स्पष्ट की है। यह धारणा उसके उन विचारों से भिन्न है जो उसने अपनी पुस्तक *General Theory* में स्फीति के संबंध में प्रस्तुत किए हैं। General Theory में वह शुरू में अल्प-रोजगार संतुलन से चलता है, परन्तु How to Pay for the War में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति से शुरू करता है। उसकी परिभाषा के अनुसार स्फीति अन्तराल योजनाबद्ध व्यय का वह आधिक्य है जो स्फीति-पूर्व अथवा आधार कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन से बढ़ जाता है। लिप्सी (Lipsey) के मतानुसार, "आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगा, वही मात्रा स्फीति अन्तराल होगी।" (The inflationary gap is the amount by which aggregate expenditure would exceed aggregate output at the full employment level of output.) क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने स्फीति का मुख्य कारण यह बताया है कि पूर्ण रोजगार स्तर दिया हुआ होने पर मुद्रा का परिमाण बढ़ जाता है। दूसरी ओर केन्ज ने पूर्ण रोजगार के स्तर पर व्यय के आय से बढ़ जाने को स्फीति का कारण माना है। समस्त व्यय जितना अधिक होगा, अन्तराल भी उतना ही अधिक होगा और स्फीति की गति भी उतनी ही अधिक तेज होगी। स्थिर औसत बचत प्रवृत्ति दी हुई होने पर, पूर्ण रोजगार स्तर पर मुद्रा-आय में वृद्धि से जब पूर्ति से मांग बढ़ जाएगी, तो परिणामस्वरूप स्फीति अन्तराल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार केन्ज ने स्फीति अन्तराल धारणा को उन प्रमुख निर्धारकों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जो कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि लाते हैं।

एक उदाहरण की सहायता से स्फीति अन्तराल की व्याख्या की जा रही है। मान लीजिए कि स्फीति-पूर्व कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 200 करोड़ रु. है। इसमें से 80 करोड़ रु. सरकार खर्च करती है। इस प्रकार स्फीति-पूर्व कीमतों पर जनता को उपभोग के लिए 120 (= 200 – 80) करोड़ रु. का उत्पादन उपलब्ध है। परन्तु पूर्ण रोजगार स्तर पर चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय 250 करोड़ रु. है। मान लीजिए कि सरकार कर लगाकर 60 करोड़ रु. ले लेती है और प्रयोज्य (disposable) आय के रूप में 190 करोड़ रु. छोड़ देती है। इस प्रकार, 120 करोड़ रु. के उपलब्ध उत्पादन पर खर्च करने के लिए 190 करोड़ रु. की राशि विद्यमान है जिससे 70 करोड़ रु. का स्फीति अन्तराल उत्पन्न हो जाता है।

Scanned with CamScanner

1. चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय = रु. 250 करोड़
2. कर = रु. 60 करोड़
3. प्रयोज्य आय = रु. 190 करोड़
4. स्फीति-पूर्व कीमतों पर GNP = रु. 200 करोड़
5. सरकारी व्यय = रु. 80 करोड़
6. स्फीति-पूर्व कीमतों पर उपभोग = रु. 120 करोड़

के लिए उपलब्ध उत्पादन स्फीति अन्तराल (मद 3-6) = रु. 70 करोड़

वास्तव में, 190 करोड़ रु. की सारी प्रयोज्य आय खर्च नहीं की जाती, इसका कुछ भाग बचा लिया जाता है। मानलीजिए, यदि इसका 20 प्रतिशत (38 करोड़ रु.) बचाया जाता है, तो 120 करोड़ रु. की वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न करने को 152 करोड़ (190-38 करोड़) रु. बचेंगे। इस प्रकार वास्तविक स्फीति अन्तराल 70 करोड़ रु. की बजाय 32 करोड़ (152-120 करोड़) रु. होगा।

स्फीति अन्तराल चित्र 13.3 में दिखाया गया है। यहां Y_F आय का पूर्ण रोजगार स्तर है, 45° की रेखा समस्त पूर्ति का एवं $C + I + G$ रेखा उपभोग, निवेश एवं सरकारी व्यय (या समस्त मांग वक्र) के इच्छित स्तर का दर्शाती है। अर्थव्यवस्था का समस्त मांग वक्र $C+I+G = AD$ बिन्दु E पर 45° रेखा (AS) को आय स्तर OY_1 पर काटती है जो पूर्ण रोजगार आय स्तर OY_F से अधिक है। वह राशि, जिसके द्वारा समस्त मांग (Y_FA) पूर्ण रोजगार आय स्तर पर समस्त पूर्ति (Y_FB) से अधिक होती है, स्फीति अन्तराल है। यह चित्र 13.3 में AB है। जब संसाधन पूर्ण रोजगार पर होते हैं तो कुल व्यय की अधिक मात्रा स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार, स्फीति अन्तराल अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव लाता है जो अधिक समस्त मांग के कारण होते हैं।

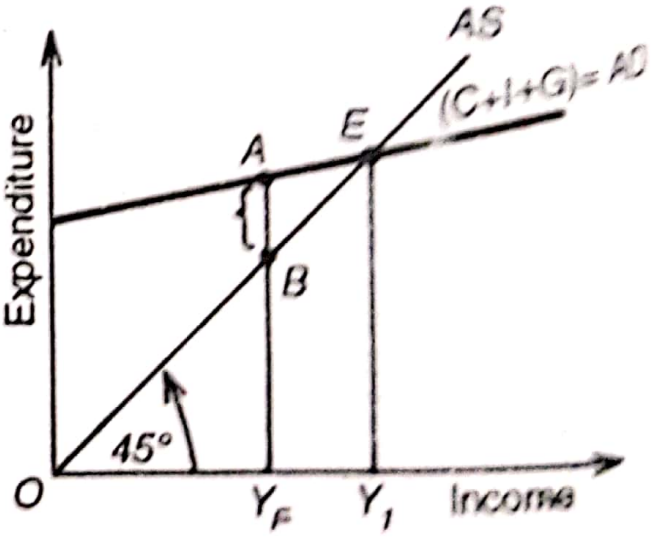

चित्र 13.3

स्फीति अंतराल कैसे समाप्त किया जा सकता है? (How can the inflationary gap be wiped out?)

स्फीति अंतराल को निम्न उपायों से समाप्त किया जा सकता है। *प्रथम,* करों को इस हद बढ़ाकर कि समस्त मांग घट जाय, स्फीति अन्तराल समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह अवस्फीतिकारी प्रवृत्तियां ला सकती है।

दूसरा हल यह है कि उपलब्ध उत्पादन का मूल्य बढ़ाकर उसे प्रयोज्य (disposable) आय के बराबर कर दिया जाय। जब समस्त मांग बढ़ती है तो व्यवसायी उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा श्रमिक लगाता है। लेकिन यहां वर्तमान मुद्रा मजदूरी पर पूर्ण रोजगार होने के कारण, वे अपने साथ काम करने के लिए अधिक श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए अधिक मुद्रा मजदूरी देते हैं। चूंकि यहां पहले से ही पूर्ण रोजगार होता है, इसलिए मुद्रा मजदूरियों में वृद्धि कीमतों में आनुपातिक वृद्धि लाती है। *तीसरा,*

Scanned with CamScanner

अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि साधन पहले से ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर होते हैं। चौथा, इसलिए स्फीति अन्तराल कराधान बढ़ाकर एवं व्यय को कम करके समाप्त किया जा सकता है। मौद्रिक नीति का भी प्रयोग मुद्रा कोष को घटाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन केन्ज अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय के पक्ष में नहीं थे।

आलोचनाएं (Criticisms)

फ्रीडमैन[1] कूपमैन्ज,[2] सलाण्ट[3] तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने स्फीति अन्तराल धारणा की आलोचना की है।

1. स्फीति अन्तराल विषयक विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ण रोजगार कीमतें ऊपर की ओर लचीली होती हैं। दूसरे शब्दों में, वे बाजार में वस्तुओं की अति मांग के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसकी यह मान्यता भी है कि जब कीमतें बढ़ रही हों तो मुद्रा-मजदूरी निश्चल (sticky) होती है परन्तु *GNP* में लाभों का भाग बढ़ जाता है। इसलिए यह धारणा अति-मांग स्फीति से सम्बद्ध है जिसमें लाभ-स्फीति विद्यमान रहती है। इसके परिणामस्वरूप, मांग तथा लागत स्फीतियां मिश्रित हो गई हैं।

Excess demand model of Inflation

2. बैण्ट हैन्सन ने केन्ज़ की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने स्फीति अन्तराल को केवल वस्तु बाजार तक सीमित कर दिया है और साधन बाजार के कार्यभाग की उपेक्षा की है। हैन्सन के मतानुसार, स्फीति अन्तराल वस्तु बाजार में और साधन बाजार में अति-मांग का परिणाम होता है।[4]

3. स्फीति अन्तराल विश्लेषण स्थैतिक है परन्तु स्फीतिकारी घटनाएं गत्यात्मक होती हैं। केन्ज़ ने उन्हें गत्यात्मक बनाने के लिए स्वयं सुझाव दिया था कि आय की प्राप्तियों और व्ययों से संबंधित समय अंतर या पश्चताएं शामिल किए जाएं। कूपमैन्ज ने पश्चतायों (lags) तथा समय की प्रति इकाई कीमत वृद्धि की दर के बीच संबंधों का विकास किया है। उसने व्यय पश्चतायों एवं मजदूरी-समायोजन पश्चतायों की सहायता से दिखाया है कि स्फीति की गति थोड़ी हो जाती है अर्थात् स्फीति अन्तराल कम हो जाता है।

4. होल्जमैन ने पूर्ण रोजगार स्थिति पर गुणक तकनीक को लागू करने के लिए केन्ज़ की आलोचना की है। उसके अनुसार, पूर्ण रोजगार और स्फीति की अवधियों में गुणक तकनीक पर्याप्त नहीं है। यह आय वितरण में परिवर्तनों को पृथक करता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में, राष्ट्रीय उत्पाद में एक वर्ग का हिस्सा केवल किसी दूसरे की कीमत पर ही बढ़ाया जा सकता है।[5]

5. स्फीति अन्तराल की एक और कमी यह है कि वह इस तरह की प्रवाह धारणाओं से सम्बद्ध है जैस चालू आय, व्यय, उपभोग और बचत। वास्तव में, पूर्ण रोजगार स्तर पर कीमतों का बढ़ना केवल चालू वस्तुओं की कीमतों तक ही सीमित नहीं होता। फिर, क्योंकि प्रयोज्य आय चालू आय तथा करों का अन्तर होती है, इसलिए हो सकता है कि प्रयोज्य आय में पिछली अवधियों की आय से निष्क्रिय शेष भी सम्मिलित हों।[6]

---

1. M. Friedman, "Discussion of the Inflation of the Gap", *A.E.R.*, Vol. 32, 1942.
2. T. Koopmans, "The Dynamics of Inflation", *R.E.S.*, Vol. 24, 1942.
3. W. Salant, "The Inflationary Gap, Meaning and Significance for Policy Making", *A.E.R.* Vol. 32, 1942.
4. Bent Hansen, *A Study in the Theory of Inflation*, 1951.
5. F. D. Holzman, "Income Determination in Open Inflation", *R.E.S.*, Vol. 32, 1950.
6. R.N. Mitra and H. Roy, *A Tract on Money*, 1958, p. 56.

Scanned with CamScanner

महत्व (Importance)

इन आलोचनाओं के बावजूद, पूर्ण रोजगार स्तर पर बढ़ती कीमतों और स्फीति नियंत्रण के नीति उपायों की व्याख्या करने में स्फीति अन्तराल की धारणा बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

1. स्फीति अंतराल की धारणा वस्तु मार्के से संबद्ध है। यह बताती है कि मुद्रा का स्फीति के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है अर्थात् यह सुझाव नहीं देती कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि स्फीति अंतराल का कारण है, बल्कि व्यय के बढ़ने को स्फीति अंतराल का कारण बताती है।

2. यह धारणा बताती है कि जब एक बार पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाता है तो बढ़े हुए व्यय द्वारा उत्पन्न अति मांग के कारण कीमतें बढ़ती हैं। परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में सब संसाधन पूर्णरूप से रोजगार पर लगे हैं। इससे स्फीति आती है। व्यय जितना ही अधिक होगा, अन्तराल भी उतना ही बड़ा होगा और स्फीति की गति भी उतनी ही अधिक तेज होगी।

3. नीति उपाय के रूप में यह धारणा सुझाव देती है कि स्फीति को नियंत्रित करने के लिए समस्त मांग घटानी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कर बढ़ाकर बचत का बजट तैयार किया जाए। यह इस बात के भी पक्ष में है कि उपभोग व्यय घटाने के लिए बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए।' राष्ट्रीय आय, निवेश व्ययों तथा उपभोग व्ययों जैसे समूहों की शब्दावली में स्फीति अन्तराल का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह बताता है कि करों, सार्वजनिक व्ययों, बचत आन्दोलनों, साख नियंत्रण, मजदूरी समायोजन से संबंधित सार्वजनिक नीति को कौन निर्धारित करता है? संक्षेप में यह वे सब विचारणीय प्रति-स्फीति (anti-inflationary) उपाय बताता है जो उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति तथा निवेश प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं जो (प्रवृत्तियां) इकट्ठी मिलकर सामान्य कीमत-स्तर को निर्धारित करती हैं।[1]

Scanned with CamScanner